

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग—९
संख्या— 719 / 27—९—२००९(९) / स्टाम्प—५३ / २००९
देहरादून, ०६ अक्टूबर, २००९

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित (समय—समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 के उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचनाओं संख्या—२९९ / XXVII(९) / स्टाम्प / २००६, दिनांक १८ अगस्त, २००६ को अधिकमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में बीस लाख रुपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25 प्रतिशत) तक कमी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परन्तु यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में बीस लाख रुपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जायेगी और बीस लाख रुपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरुष या उससे अधिक पुरुषों के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख में यदि स्त्री/स्त्रियों का अंश विनिर्दिष्ट हो, तो ऐसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क में स्त्री/स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक कमी कर दी जायेगी, किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकार्य न की गयी हों।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन,)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक : 719(१) / २७—९—२००९(९) / स्टाम्प—५३ / २००९ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
२. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
३. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
४. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
५. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग ४ खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी २०० प्रतियां वित्त अनुभा—९ में उपलब्ध करा दें।
६. न्यायय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
७. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
८. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल०एम० पन्त)
सचिव।